[श्री जीवा भाई]

को मजदूरी का भुगतान अभी तक नही हुआ है । मजदूरों को भुगतान करने के क्रम में अभी तक अपर्याप्त प्रयत्न किए गए हैं । मजदूर पेमेंट नही मिलने से परेशान हो गए हैं । इससे हमारे प्रधान मंत्री जी के बारह सूत्री अकाल कार्यक्रम की अवहेलना हो रही है । अत. राज्य सरकार को निदेश दिया जाए कि वह बढ़ा हुआ मजदूरों का भुगतान अविलम्ब कराए ।

(iii) STEPS TO MEET THE LEGITIMATE DEMANDS OF HANDLOOM INDUSTRY.

SHRI K. KUNHAMBU (Cannanore): Sir, the handloom weavers of Kerala have gone on a strike demanding protection to the handloom industry and higher wages and other benefits for the workers.

Many organisations connected with the handloom industry have made repeated representations to the Central Government demanding a reduction in the price of yarn. The Kerala Government itself has requested the Centre to do something about it But, strangely enough, the Central Government went on increasing the price of yarn. In March last, the Prime Minister had given an assurance that the matter would be given sympathetic consideration. But the Government has not cared to implement that assurance. The price of yarn has gone upto between 45 and 47 per cent. In this situation, it is essential that the price be brought down to 1978 level, and it has to be maintained at this level for some more time so that the handloom industry is not ruined.

The handloom industry is a decentralised one in many areas. As a result of that, the workers are deprived of minimum wages and other benefits. The Central Government should take initiatives to re-organize this industry on factory lines and on force national minimum wages.

I, therefore, request the Government to take immediate steps so that the legitimate demands of the workers in the handloom industry are met.

(iv) REPORTED NON-AVAILABILITY OF SUGAR AND OTHER RATIONED ITEMS AT FAIR PRICE SHOPS IN NORTH AVENUE AND OTHER PARTS OF DELHI.

श्री रामाशंकर कौशिक (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, राशन की दुकानों में चीनी नहीं । नई दिल्ली के प्रेसिडेन्ट एस्टेट स्थित मार्किट में राशन की दो दूकानें हैं । उनसे अन्य नागरिकों के अतिरिक्त नार्थ एवेन्यु में रहने वाले संसद-सदस्यों को भी राशन, चीनी आदि वस्तुएं मिलती हैं । परन्तु आश्चर्य है कि जून माह में उक्त दूकानों के काउंटरों उपभोक्ताओं को एक दाना भी चीनी नसीब नहीं हुई । अधिकांश उपभोक्ताओं को खुले बाजार से सात रुपये किलो के भाव से चीनी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है । अत. उनकी कठिनाइयों का अनुमान आसानी के साथ लगाया जा सकता है ।

उपभोक्ताओं को माह मे दो बार चीनी मिलती है, पर जून माह में एक बार भी नही मिली । दूकानदार बराबर यही जवाब देते है कि स्टाकिस्ट ने उन्हें चीनी की सप्लाई नही की है, पाहक चाहे तो अन्यत्र जा सकते है । ग्राहको को इस माह मे यानी जुलाई मे भी अब तक चीनी का दर्शन नही हुआ है । राशन की भी यही स्थिति है, कभी चावल मिलता है तो गेहू नही और गेहू मिलता है तो चावल नही ।

चीनी नही मिलने की शिकायत एक सासद ने लोक-सभा के अध्यक्ष से चार बार की, सासद ने आपूर्ति मंत्री से भी कहा । लोक सभा अध्यक्ष ने आपूर्ति मत्री को इस बारे मे पत्र भी लिखा, पर जवाब नदारद । 27 जून को कुछ सांसदों ने दिल्ली में चीनी के अभाव तथा मूल्य वृद्धि का महत्वपूर्ण सवाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, उक्त दुकानों की भी चर्चा की गई, जवाब मे कृषि मत्री ने चीनी की कठिनाई दूर करने का आश्वासन भी दिया, परन्तु दुःख है कि उनका आश्वासन कोरा आश्वासन बन कर रह गया ।

दिल्ली प्रशासन के लिये यह विचार करने योग्य बात है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी संसद्-सदस्यो समेत आम उपभोक्ताओ को राशन की दूकानो से चीनी नही मिल रही है । दुकानदार भागा फिर रहा है । इस सम्बन्ध मे आपूर्ति मंत्री को सदन में वक्तव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये ।

(v) STEPS TO CLEAR THE PENDING CASES IN CALCUTTA INDUSTRIAL TRIBUNAL

SHRI SUSHIL BHATTACHARYYA (Burdwan): A good number of cases are pending at Calcutta Industrial

Tribunal and Labour Court and Establishment of Tribunal since 1977 and many cases of dismissals and non-employment are to be decided quickly to give relief to the victimised workers. The Presiding Officer of the Calcutta Tribunal has retired on the 31st December, 1979 and since then the post is lying vacant. In 1979 the Coal Mines Employees' Union requested the Central Government to establish a Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Asansol area and the Government gave due consideration in this regard. The Calcutta Tribunal-cum-Labour Court is overburdened with pending cases and no speedy decision is coming on the cases, as a result workers are very much suffering.

Under the circumstances, I urge upon the government that the vacant post of the Presiding Officer at Calcutta may be filled up immediately and also certain cases may be referred to the Dhanbad Tribunal which is nearer to the Coalfields of Eastern Coalfields and less expensive than the Calcutta office and Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Asansol.

(vi) MEASURES TO PROVIDE NECESSARY FACILITIES FOR PLANTATION OF PADDY IN DROUGHT AFFECTED AREAS OF BIHAR.

श्री डूमरलाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उपस्थित करते हुए मुझे निवेदन करना है कि बिहार के काफी हिस्सों में, खासकर पूर्णिया जिले के नेपाल सीमा स्थित भाग में, सूखे के कारण धान को रोपने का कार्य एकदम ठप्प हो गया है। किसानों की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय हो गई है। उन्हें पटवन के लिए न तो बिजली की आपूर्ति की जाती है और न नहरों के द्वारा ही पटवन का प्रबन्ध है। जहां भी नहर द्वारा पटवन हो सकता है, वहां भी नहर को बन्द कर पटवन रोक दिया गया है। नहर अधिकारियों से नहर का पानी पटवन हेतु देने का अनुरोध करने पर उनका कहना है कि चूंकि अभी पानी में प्रति-क्यूसेक लगभग 35 प्रतिशत सिल्ट है, अतः जब तक यह सिल्ट बैठ नहीं जाता, नहर द्वारा पटवन नहीं किया जा सकता। सिल्ट छांट कर स्वच्छ पानी देने का कोई निर्धारित समय वे नहीं बताते। बल्कि उनका कहना है कि यदि कोसी नदी के उदगम एवं ऊपर के भागों में पुनः बाढ़ आई, तो पटवन आरम्भ करने की अवधि में और भी विलम्ब होगा। लोगों के धान के बिचड़े खेतों में सूख रहे हैं। अधिक उत्पादन देने वाले किस्मों के धान एवं अन्य फसलों के लिए बिचड़े उगाहने, उखाड़ने एवं खेतों में पुनः रोपनी को निर्धारित अवधि के भीतर ही होना चाहिए, अन्यथा फसल का उत्पादन लाभप्रद नहीं रहता है। अतः ऐसी परिस्थिति में किसानों को, खासकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसानों को, भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ेगा एवं राष्ट्रीय पैमाने पर उत्पादन की व्यापक क्षति होगी।

अतः सरकार से अनुरोध है कि सरकार (1) कोसी एवं अन्य नहरों द्वारा, जहां अभी भी पटवन आरम्भ नहीं किया गया है, तुरन्त पटवन आरम्भ करने का आदेश दे, (2) उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर कृषि-कार्य में लगे नलकूपों में बिजली की आपूर्ति का अविलम्ब प्रबन्ध करे, (3) डीजल इंजिनों की यथाशीघ्र व्यवस्था कर किसानों को मुहैया कराये एवं उसके लिए डीजल, मोबिल आयल आदि की आपूर्ति की भी व्यवस्था करे, और (4) सरकारी विभागों द्वारा भी छोटे एवं सीमान्त किसानों के खेतों में डीजल इंजिनों द्वारा पटवन का प्रबन्ध किया जाय, ताकि उत्पादन की व्यापक राष्ट्रीय क्षति से देश को बचाया जा सके।

इसमें अविलम्ब व्यवस्था की आवश्यकता है। अतः सिंचाई विभाग स्वयं एवं राज्य सरकार को आदेश देकर इसकी शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करे।

12.54 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL COMPANY LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE,

AND ....

NATIONAL COMPANY LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up the statutory resolution to be moved by Shri T. R. Shamanna. We are taking up items 10 and 11 together.